ISSN-0970-0718

जागृति

वर्ष:60 अंक:4 मुम्बई मार्च 2016

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ग्रामीण औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई

ISSN-0970-0718

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

वर्ष 60 अंक 4 मुम्बई मार्च 2016

सम्पादक मंडल

अध्यक्ष
अरुण कुमार झा

सम्पादक
के. एस. राव

उप सम्पादक
सुबोध कुमार

अवर उप सम्पादक
अमृता सोम मुखर्जी

अवर हिन्दी अनुवादक
सरस्वती खनका

वरिष्ठ कलाकार - अनुप खोडस्कर

कलाकार - दिलीप पालकर

के. सुब्बाराव, द्वारा प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम
निदेशालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय,
3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056
के लिए प्रकाशित
टेलिफैक्स: 022-26719465
ई-मेल: jagritikvic@gmail.com वेबसाईट: www.kvic.org.in

प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड,विले पार्ले (पश्चिम),
मुम्बई - 400 056 में प्रकाशित
सम्पादक: के. सुब्बाराव राव

सदस्यता शुल्क

वार्षिक सदस्यता शुल्क	:	रू. 100/-
वर्ष के लिये सदस्यता शुल्क	:	रू. 250/-

इस अंक में...

समाचार सार 3 से 26

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए गौरव के क्षण.....
एमएसएमई से भारत बनेगा सोने की चिड़िया -कलराज मिश्र.....
खादी उत्पादों की बिक्री हेतु आयकर विभाग, मुंबई से अनुबंध कर.....
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह का.....
फरीदाबाद में राज्य स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में 1.21 करोड़.....
बाज़ार में बड़ी हिस्सेदारी हेतु आयोग बना रहा व्यापक योजना.....
देश की प्रगति में खादी और ग्रामोद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका.....
दुनिया के सबसे बडे चरखे के प्रदर्शन हेतु आयोग हो रहा है तैयार.....
सौर ऊर्जा संचालित 'चरखा' व नए मार्केटिंग तकनीकों के सहारे होगा.....
रेल बजट में खादी क्षेत्र से भी सहयोग लेने पर जोर.....
खादी में नजर आएंगे महाराष्ट्र राज्य के होमगार्ड.....
पोर्ट ब्लेयर में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उद्यमिता विकास.....
बंगलुरु में हिन्दी कार्यशाला आयोजित.....
एन.आई.एफ.टी. के छात्रों ने खादी उत्पादन संबंधी गतिविधियों को देखा...
छत्तीसगढ़ में निजी स्कूल के नन्हे-मुन्ने पहनेंगे खादी.....
विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक की झलकियां.....
श्री के.के.जालान ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव.....
आयोग ने भारतीय विज्ञान काँग्रेस में भाग लिया.....
महिला सशक्तिकरण का माध्यम बना सोलर चरखा -पुष्पमित्र.....

खादी क्षेत्र की सुर्खियां 27 से 29

आयोग के लिए गौरव के क्षण

भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 6 फरवरी, 2016 को विशाखापटनम में आयोजित "इण्टरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2016 (आईएफआर-16)" प्रदर्शनी में खादी इण्डिया के स्टॉल का अवलोकन किया, जहां उन्होंने पोंडुरू खादी बनने की प्रक्रिया का जीवांत प्रदर्शन एवं खादी ग्रामोद्योगी उत्पादों की विशेष श्रृंखला को देखा।

चंडीगढ़ में एमएसएमई का क्षेत्रीय कॉन्क्लेव आयोजित

एमएसएमई से भारत बनेगा सोने की चिड़िया

- कलराज मिश्र

एमएसएमई इकाइयां ही देश के विकास की रीढ़ हैं। ये लघु उद्योग ही भारत को विकसित बनाएंगे और देश को पुन: सोने की चिड़िया वनाएंगे। प्राचीन भारत में छोटे और कुटीर उद्योगों ने ही भारत को सोने की चिड़िया वनाया था। अमेरिका, यूरोप और जापान को विकसित देश इन लघु इकाइयों ने ही बनाया है-यह वात केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्योग (एमएसएमई) मंत्री श्री कलराज मिश्र ने 19 फरवरी 2016 को सीआईआई चंडीगढ़ में आयोजित एमएसएमई (उत्तरी क्षेत्र) के एक क्षेत्रीय कॉन्क्लेव में एक संवाद के दौरान कही।

माननीय मंत्री महोदय ने इस अवसर पर यह भी कहा कि देश तभी विकसित बनेगा जब एमएसएमई इकाइयां आगे बढ़ेंगी और वे अपने दायित्व का निर्वाह करें। एमएसएमई के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार बीमार इकाइयों के पुनर्वास, प्रशिक्षण और टूल रूम बढ़ाने पर विचार कर रही है। देश में 15 टूल रूम और बनाए जाएंगे। अभी देश में इनकी संख्या 18 है।

माननीय केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश - पावर सरप्लस राज्य हैं और इन राज्यों में औद्योगिक क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। सकल घरेलू उत्पाद में 7.3 प्रतिशत विकास दर है। देश में एमएसएमई क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे पास 4 करोड़ 70 लाख पंजीकृत और गैर-पंजीकृत औद्योगिक इकाईयां हैं, जो देश में 12 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं और जिनका निर्यात में 42 प्रतिशत का योगदान है।

मंत्री महोदय ने भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी योजनाओं को प्रभावी ढ़ंग से कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं,

ने आग्रह किया है कि एमएसएमई क्षेत्र के निर्यात–विकास को बढ़ाने के लिए पूर्वी गलियारे के रूप में-वाघा-अटारी सीमा के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए एक सुविधा होनी चाहिए। वर्तमान में 127 वस्तुओं/उत्पादों के लिए एक व्यापार है, इन्हें काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है और जहां लगभग 6000 वस्तुओं तक व्यापार किया जा सकता है। उन्होंने माननीय मंत्री से उपरोक्त मदों को शामिल करने के लिए मंत्रालय स्तर पर बातचीत करने का अनुरोध किया।

श्री मदन मोहन मित्तल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब समृद्ध राज्य है एवं निवेश के लिए तथा व्यापार हेतु एक असीम और पर्याप्त अवसर का स्थान है। पंजाब राज्य में व्यापक संभावनाओं को व्यक्त करते हुए मंत्री ने बताया कि पंजाब बिजली सरप्लस राज्य है और सुप्रशासित होने के साथ-साथ यह राज्य अच्छी तरह

इस बात की निगरानी रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए इन योजनाओं की उचित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और शून्य दोष और शून्य प्रभाव नीति को आचरण में प्रभावी बनाना चाहिए। हम केवल एमएसएमई क्षेत्र के विकास के साथ आगे बढ़ सकते हैं, बड़े उद्योगों की स्थापना से नहीं।

एमएसएमई (उत्तरी क्षेत्र) का एक क्षेत्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन सीआईआई चंडीगढ़ में 19 फरवरी 2016 को किया गया। श्री अनिरुद्ध तिवारी, प्रमुख सचिव ने अपने स्वागत भाषण में माननीय मंत्री को अवगत करवाया कि एमएसएमई क्षेत्र, उद्योग की रीढ़ है। यह क्षेत्र रोजगार पैदा करने के साथ-साथ सकल घरेलू उत्पाद की दर में वृद्धि करने में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इसमें 1.6 लाख एमएसएमई क्षेत्र हैं जिसमें लगभग 11 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। श्री तिवारी

से रेल सेवाएं एवं सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। पंजाब सरकार ने पहले से ही कौशल विकास योजना के लिए 4 प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 391 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें 1,209 वस्तुओं के व्यापार के लिए पाकिस्तान सड़क मार्ग को नहीं अपनाया जा सकता है। उन्होंने अनुरोध किया कि मामले को पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया जा सकता है। अटारी, हुसैनपुर, फजिलाका मार्ग का उपयोग सीलबंध कंटेनर के माध्यम से व्यापार की इजाजत देने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आबादी का 60 प्रतिशत के खाद्य मांग को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ पंजाब को प्रोत्साहन के रूप में बराबरी दी जानी है और हम भी चीन से चुनौती का सामना कर रहे हैं। पंजाब राज्य के लिए रियायतें बहुत आवश्यक हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी समाप्त कर दिया जा सकता है। जिसके लिए जीएसटी लागू किया जाना चाहिए और एमएसएमई क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए चीन से निर्यात किये जाने वाले उत्पादों पर आयात शुल्क में वृद्धि की जानी चाहिए। बटाला से बिएस के मध्य रेल मार्ग होना चाहिए। वर्तमान में पंजाब के मौजूदा जिला उद्योग केंद्रों में 232 कर्मचारी हैं और औद्योगिक क्षेत्रों को एक गति प्रदान करने के लिए इन जिला उद्योग केंद्रों को मजबूत करने की जरूरत है। पंजाब की भूमि गुरुओं की भूमि है और वे हमें, कार्य ही पूजा है, का उपदेश देते हैं।

क्षेत्रीय सम्मेलन के अवसर पर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए उनकी कृतज्ञता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 7- 8 मार्च, 2016 से आयोजित होने वाले वैश्विक सम्मेलन में भाग लेने के लिए माननीय मंत्री के साथ अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा, हमने विभिन्न देशों का दौरा किया और उद्यमियों को उपक्रमों की स्थापना के लिए उन्हें हरियाणा आमंत्रित किया है। हमने हरियाणा में निवेश के लिए 1 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है, जबकि हमें 2.15 लाख करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और जिसके लिए पहले से ही 1.50 लाख करोड़ के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये हैं। उन्होंने कहा कि 2,300 करोड़ निवेश और 50000 व्यक्तियों के रोजगार सृजन के साथ 2,835 एमएसएमई इकाइयों को स्थापित कर प्रति व्यक्ति निवेश आय में पिछले 15 महीनों से हरियाणा देश का नम्बर एक राज्य है।

श्री के.के. जालान, आईएएस, सचिव (एमएसएमई) ने जोर देते हुए कहा कि हमें अन्य राज्यों से सीखना चाहिए और हमें ऐसे कदम अपनाने होगें, जो हमारे उद्योग के लिए उपयोगी होते हैं। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि 32 मंत्रालयों में 310 योजनाएं हैं और इन योजनाओं के प्रति लोगों के बीच तत्पर प्रयासों से जागरूकता पैदा की जानी चाहिए, ताकि इन योजनाओं को प्रभावी और कारगर ढंग से लागू किया जा सके।

खादी उत्पादों की बिक्री हेतु आयकर विभाग, मुंबई से अनुबंध कर आयोग ने शुरू की एक नई पहल

आयकर भवन, मरीन लाइन्स, मुंबई के उपभोक्ता स्टोर्स में खादी ग्रामोद्योगी उत्पादों का विक्री आउटलेट एवं एक विशेष प्रदर्शनी का उदघाटन करते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री वी के सक्सेना, अध्यक्ष ने कहा कि आयकर विभाग के साथ अनुबंध के रूप में केवीआईसी के इतिहास में यह एक नई शुरुआत है। उन्होंने कहा कि "मेक इन इंडिया" के माध्यम से ही ग्रामीण भारत का विकास संभव है। उन्होंने कहा,"ए जीरो कार्बन फुट प्रिंट" खादी(शून्य कार्बन रहित खादी), सबसे वेहतर पर्यावरण के अनुकूल वस्त्र है।

उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि केवीआईसी ही केवल एकमात्र ऐसा संगठन है जो प्रशिक्षण, ऋण सुविधा, उत्पादन, विपणन आदि क्षेत्रों में जो शुरू से लेकर अंत तक पूरा सहयोग प्रदान करता है। आज, केवीआईसी 12.5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है तथा जिसने 37,642.24 करोड़ रुपये

की बिक्री दर्ज की है।

श्री देवेन्द्र सक्सेना, प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र से संबद्ध 12.5 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन जैसे समाजार्थिक दायित्व का समर्थन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि खादी का पुनरुद्धार होना एक बड़े गर्व की बात है।

श्री अरुण कुमार झा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस अवसर पर दोहराया कि खादी हमारी विरासत का प्रतीक है और मुंबई शहर के लिए सबसे उपयुक्त वस्त्र है। खादी धीरे-धीरे आज एक लोकप्रिय फैशन स्टेटमेंट बनता जा रहा है।

इस अवसर पर श्री के.एस. राव, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उपस्थित गणमान्य लोगों का स्वागत करते हुए खादी और इसकी गुणवत्ता एवं लाभों के बारे में सभी को जानकारी दी। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि इस अनुबंध से कार्यालय जाने वाले बहुत से लोगों के बीच खादी लोकप्रिय होगी और जिससे खादी की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न अन्य सरकारी कार्यालयों और परिसरों में भी इसी तरह के आउटलेट्स खोले जाएगें। ■■

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री श्री गिरिराज सिंह का एक दिवसीय अहमदाबाद दौरा

श्री गिरिराज सिंह, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 17 जनवरी 2016 को अपने एक दिवसीय अहमदाबाद प्रवास के दौरान पूरे देश में सोलर चरखे के कार्यान्वयन हेतु एक बैठक की, जिसमें माननीय मंत्री महोदय ने सोलर चरखा एवं सोलर पावरलूम के संबंध में राज्य निदेशक श्री संजय हेडाऊ तथा खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। बैठक में उन्होंने डेनिम जीन्स उत्पाद के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

फरीदाबाद में राज्य स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में 1.21 करोड़ रूपये से ज्यादा की बिक्री हुई

राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अम्बाला छावनी द्वारा एक राज्य स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन दिनांक 30.01.2016 से 16.02.2016 तक हुड्डा ग्राउंड, खेल परिसर के सामने, सैक्टर-12, फरीदाबाद में किया गया।

इस प्रदर्शनी का समापन दिनांक 16.02.2016 को श्री विनय कुमार सक्सेना, माननीय अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री लक्ष्मीदास, पूर्व अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, श्री वी.के. नागर, राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अम्बाला छावनी, जिला उद्योग केन्द्र, हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एवं बैंकों के अधिकारीगण के अतिरिक्त बड़ी संख्या में खादी ग्रामोद्योगी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण एवं कत्तिन, बुनकर कारीगर उपस्थित थे।

श्री विनय कुमार सक्सेना, अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस अवसर पर सर्वप्रथम प्रदर्शनी में भाग लेने वाली सभी संस्थाओं एवं इकाईयों को शुभकामनांए देते हुए कहा कि खादी में वो शक्ति है जिसे हर घर में आजीविका

के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। आज का दौर तकनीक का दौर है और यही तकनीक हमारी प्रगति में मददगार भी है। जिस सोलर चर्खे को हाल ही में विकसित किया गया है ऐसे लगभग 2000 चर्खे वितरित करने की योजना है क्योंकि जो

कत्तिन अभी 100 से 125 रूपये मजदूरी पा रही है उसकी मजदूरी में वृद्धि हो सके और यह मजदूरी 300 रूपये तक हो सकती है। उन्होंने बताया कि आयोग में उनके कार्यकाल की इस अवधि तक आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित कर लगभग 70 करोड़ रूपये के सरकारी आपूर्ति के आदेश प्राप्त किये हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस तरह की प्रदर्शनियों को नियमित रूप से लगाया जाएगा, नये नये लोगों को खादी के कार्य से जोड़ा जाएगा, पूरे देश में 20 नये खादी बिक्री भवन खोलने के प्रयास जारी हैं एवं आवश्यकता के अनुसार आयोग फ्रैन्चाईज़ी देने पर भी विचार कर रही है।

उन्होने आह्वान किया कि खादी क्षेत्र का भविष्य उज्ज्वल है और हम सबको इसे सशक्त और सबल बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास करने चाहिए। उन्होने कत्तिन, बुनकरों द्वारा किये गये फैशन शो की सराहना की और उम्मीद जताई कि ऐसे प्रयासों से निश्चित तौर पर क्षेत्र में नयापन आएगा। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि इस प्रदर्शनी में दिनांक 15.02.2016 तक 1 करोड़ 21 लाख रूपये की खादी ग्रामोद्योगी उत्पादों की बिक्री हुई है जो पिछली प्रदर्शनी की अपेक्षा 20 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अम्बाला छावनी द्वारा इस प्रदर्शनी में किये गये प्रदर्शन एवं उपलब्धि की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

श्री लक्ष्मीदास, पूर्व अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने विचार रखते हुए कहा कि खादी और ग्रामोद्योग देश की आर्थिक व सामाजिक प्रगति हेतु महत्वपूर्ण है। चूंकि यह उद्योग कम पूंजी की लागत से अधिक रोजगार सृजन कर सकते हैं अत: इन्हे प्रोत्साहन देना आवश्यक है। उन्होने यह भी कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी क्षेत्र में कार्यरत् कत्तिन, बुनकर एवं अन्य कारीगरों को प्रभावित करता है।

श्री वी.के. नागर, राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अम्बाला छावनी ने अपने स्वागत भाषण में अवगत कराया कि मेक इन इण्डिया एवं स्किल इण्डिया के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग राज्य में अनेकों प्रयास कर रहा है ताकि खादी ग्रामोद्योगी क्षेत्र में उत्पादन एवं बिक्री बढ़े तथा साथ

ही नई तकनीक अपनाने से कारीगरों की आमदनी में भी वृद्धि हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 3 अक्तूबर 2014 को मन की बात कार्यक्रम में खादी को अपनाने का आग्रह किया था तब से खादी की बिक्री में निरंतर वृद्धि हुई है।

उन्होंने बताया कि राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अम्बाला छावनी द्वारा प्रदेश में खादी ग्रामोद्योगी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए अनेकों उपाय किये जा रहे हैं ताकि प्रदेश में खादी के उत्पादन व बिक्री में वृद्धि हो एवं कारीगरों की आमदनी बढ़े जैसे सभी खादी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ एक वाट्स ऍप ग्रुप बनाया गया है ताकि विचारों के आदान-प्रदान में सुविधा हो, इसके अतिरिक्त अन्य प्रयासों में संस्थाओं के पंजीकरण के नये प्रस्ताव प्राप्त करना, कमजोर एवं बन्द संस्थाओं का पुर्नजीवन करना, संस्थाओं द्वारा नये चर्खे एवं नये करघे खरीद करना, कत्तिनों एवं बुनकरों को प्रशिक्षण देना, संस्थाओं द्वारा आई.एस.ओ. प्रमाण-पत्र प्राप्त करना, नये नये डिजाईन के रेडिमेड वस्त्र तैयार करना, डेनिम खादी का उत्पादन करना, घरेलू एवं अर्न्तराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना, खादी भंडारों का नवीनीकरण कराना, नये खादी भंडार खोलना, उत्पादों के आकर्षक कैटलॉग तैयार करना, ई-कॉम का लाभ लेना, सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग, नियमित प्रचार-प्रसार, रूफटॉप सोलर पैनल लगाना, वृक्षारोपण करना, स्थानीय प्रशासन, सरकारी, गैर सरकारी संगठन एवं कालेज आदि से आपूर्ति आदेश प्राप्त करना, उत्पादन एवं बिक्री केन्द्रों पर छात्र छात्राओं के भ्रमण की व्यवस्था करना, गतिविधियों पर छोटी छोटी विडियो फिल्म बनाना एवं उत्पादों के सुन्दर व आकर्षक गिफ्ट पैक बनाना जिन्हें मुख्य उत्सव एवं अवसरों पर निजी, कार्पोरेट आदि संस्थानों से सम्पर्क कर आपूर्ति की व्यवस्था आदि शामिल हैं।

श्री नागर ने यह भी बताया कि प्रदर्शनी में सूत कताई, सूत बुनाई, कुम्भकारी कला, हाथ कागज से सुन्दर उत्पादों का निर्माण एवं काष्ठकला का जीवंत प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में गांधी जी की सुन्दर मूर्ति स्थापित की गई जिसके साथ आगन्तुकों ने बड़े आनन्द के साथ "सैल्फी विद गांधीजी" का अनुभव किया।

प्रदर्शनी के समापन समारोह में वरिष्ठ कारीगरों का सम्मान किया गया। खादी संस्थाओं को आई.एस.ओ. प्रमाण-पत्र एवं खादी मार्क प्रमाण-पत्र का वितरण किया गया। साथ ही खादी उत्पादों के कैटलॉग एवं हरियाणा राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की भूमिका पर तैयार की गई पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

आमतौर पर आयोजित होने वाले फैशन शो में नामचीन मॉडल आदि की सेवाएं ली जाती हैं लेकिन इस प्रदर्शनी में फैशन शो का आयोजन खादी ग्रामो-द्योगी क्षेत्र में कार्यरत कत्तिन, बुनकर एवं कारीगरों द्वारा किया गया जिसे सभी ने सराहा।

बाज़ार में बड़ी हिस्सेदारी हेतु आयोग बना रहा व्यापक योजना

अगले छः माह में 70 करोड़ रुपए की बिक्री करने की तैयारी में आयोग

6 फरवरी, 2016 को विशाखापटनम में आयोजित "इण्टरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2016 (आईएफआर-16)" प्रदर्शनी में खादी इण्डिया के स्टॉल पर रुई को सूत में कैसे रूपांतरित किया जाता है, इसका जीवांत प्रदर्शन खादी कत्तिनों द्वारा किया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अगले छः माह में 70 करोड़ रुपए की बिक्री करने हेतु अपनी नई रणनीति तैयार की है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने तूनी में नए बिक्री केंद्र का उदघाटन किया और उन्होंने "इण्टरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2016 (आईएफआर-16)" प्रदर्शनी में खादी इण्डिया के स्टॉल का निरीक्षण किया। अपने प्रवास के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने ने इस बात की जानकारी दी कि भारतीय रेलवे ने 40 करोड़ रु. का ऑर्डर प्रस्तुत करते हुये वृहद मात्रा में बेडशीड आपूर्ति का ऑर्डर दिया है जिसमें 6 लाख के चादरें और 8 लाख के पिलो कवर्स तथा अन्य उत्पाद शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त एयर इंडिया ने अपने ट्रेवल किट में अधिक से अधिक खादी उत्पाद शामिल करने की योजना बनाई है। यह कार्य 1026 करोड़ रुपए में पूर्व में ही संपादित हो चुका है। हम अब दोनों बिजनेस और प्रथम वर्ग के यात्रियों के लिए उत्कृष्ट खादी उत्पादों की एक श्रृंखला को प्रदान करने के लिए इस वृहद ऑर्डर की आपूर्ति की योजना तैयार कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य के डाक और तार विभाग ने 5,000 मीटर कपड़ा और 900 जोड़े सेंडल तथा इतने ही खादी जेकेट एंव 1,000 उपयोगी उत्पादों का ऑर्डर दिया है, यह जानकारी श्री विनय सक्सेना ने दी।

देश की प्रगति में खादी और ग्रामोद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका:

वी.के. सक्सेना

देहरादून, 11 जनवरी 2016: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना में खादी और ग्रामोद्योग के महत्व की भूमिका पूरे देश में प्रगति को रेखांकित करती है- यह बात खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री वी.के. सक्सेना ने अपने प्रथम देहरादून आगमन पर आयोग के राज्य कार्यालय के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योगी इकाईयों के प्रतिनिधियों के साथ आई.पी.एस. स्कूल, सेलाकुई के सभागार में हुई एक बैठक में कही।

बैठक में अध्यक्ष महोदय ने उत्तराखण्ड राज्य की खादी संस्थाओं एवं ग्रामोद्योगी इकाईयों की प्रगति की समीक्षा की तथा उद्यमियों को कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु सुझाव एवं निर्देश दिये। श्री सक्सेना ने कहा कि पूरे देश की प्रगति में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना में खादी और ग्रामोद्योगों की अहम भूमिका है। उन्होंने पूरे प्रयास से उद्यमों की स्थापना तथा उनके सफल संचालन की आवश्यकता पर बल दिया। आगे, श्री सक्सेना ने अच्छी खादी और ग्रामोद्योगी इकाईयों को प्रात्साहित करने की भी आवश्यकता बतायी। उन्होंने, भागार्थियों से ज्यादा से ज्यादा खादी उत्पादों को अपनाने का भी आह्वान किया।

बैठक में श्री आर. के. सिन्हा, माननीय सांसद(राज्य सभा), श्री दिनेश कुंजवाल, उपाध्यक्ष जलागम बोर्ड, उत्तराखंड सरकार ने भी चर्चा में भाग लिया।

इससे पहले बैठक में आयोग के राज्य निदेशक श्री ओम प्रकाश ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में आयोग द्वारा कार्यान्वित की जा रही खादी ग्रामोद्योगी गतिविधियों पर प्रस्तुतीकरण किया तथा राज्य में सूक्ष्म उद्योगों की गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला।

बैठक में आयोग के उप निदेशक श्री असद मलिक, सह निदेशक श्री ए.के.गुंज्याल सहित प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के जिला समन्वयक, तकनीकी पदाधिकारियों के अलावा खादी ग्रामोद्योगी संस्थाओं, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के उद्यमियों ने भाग लिया।

अपने राज्य दौरे के दौरान अध्यक्ष महोदय ने स्थानीय पीएमईजीपी इकाइयों का भी दौरा किया। ■■

दुनिया के सबसे बड़े चरखे के प्रदर्शन हेतु आयोग हो रहा है तैयार

आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने दिनांक 13.2.2016 को अपने अहमदाबाद कार्यक्रम के दौरान खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति का दौरा किया, एवं प्रयोग समिति में तैयार हो रहे दुनिया के सबसे बडे चरखा, जो कि एयरपोर्ट नई दिल्ली में लगाया जाने वाला है, की डिज़ाइन एवं तैयारी का मुआयना किया।

इस दौरान उनके साथ प्रयोग समिति के पदाधिकारी एवं आयोग के राज्य निदेशक श्री संजय हेडाऊ उपस्थित थे। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रयोग समिति द्वारा प्रदर्शित विभिन्न प्रकार के चरखों एवं प्रयोगशाला का भी निरीक्षण किया ।

सौर ऊर्जा संचालित "चरखा" व नए मार्केटिंग तकनीकों के सहारे होगा खादी क्षेत्र का कायाकल्प

अगरतला, 4 फरवरी , 2016: हाल ही के महीनों में तेजी से प्रगति कर रहा भारत अपनी ऊर्जा की मांगों की पूर्ति के लिए स्वच्छ एवं प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों की ओर उन्मुख हुआ है। अब भारत ने इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए भारत अपनी विश्वप्रसिद्ध 'खादी उद्योग' को सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित करना चाहता है। भारत अब खादी के उत्पादों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले चरखा को 'सौर' की शक्ति प्रदान करने का मन बना चुका है जिसके अंतर्गत 2022 तक लगभग 5 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

ज्ञात हो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक 175 गीगावाट ऊर्जा स्वच्छ स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है जिसमें सौर, पवन सहित अन्य प्राकृतिक तरीके शामिल हैं। यह प्रधानमंत्री का ही सपना है कि भारत की असली पहचान माने जाने वाली 'खादी' उद्योग को वे देश-विदेश में ऊंचे स्तर तक ले जाना चाहते हैं।

समय-समय पर प्रधानमंत्री मोदी ने खादी के कपड़ों व अन्य उत्पादों को लेकर भारतीय जनमानस के समक्ष भी अपनी बातें रखी हैं जिसमें उन्होने कहा भी है कि भले ही हम सब दुनिया भर के गारमेंट और भिन्न भिन्न तरीके के कपड़े पहनते हों लेकिन भारत की पहचान माने जाने वाले 'खादी' का एक कपड़ा तो अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। उनके इस अपील का असर भी देखने मिला जब देश के लोगों खासकर नौजवानों ने खादी के वत्रों को हाथों-हाथ लेना शुरू किया।

इस संदर्भ में देश के केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने अपनी त्रिपुरा की यात्रा के दौरान कहा, 'हम खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में जल्द ही सौर ऊर्जा से चलने वाली चरखा लाने जा रहे हैं ताकि देश भर में 2022 तक 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात में यह कहा है।"

श्री सिंह ने आगे कहा कि उन्होने इस संदर्भ में खादी एवं ग्रामोद्योग के चेयरमैन के समक्ष भी यह योजना रखी है ताकि हुए स्थानीय लोगों को काम मिल सके। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने त्रिपुरा के अगरतला में चलाये जा रहे खादी एवं ग्रामोद्योग केन्द्र का जायजा लिया और हाथ से काते जाने वाले खादी उद्योग को प्रदूषण रहित बनाने के विषय में चर्चा की।

मंत्री महोदय ने यह भी जानकारी दी कि भारत सरकार खादी उद्योग के पुनरुद्धार के लिए लगातार नए प्रयास कर रही है जिसमें फैशन डिजाइनरों के साथ गठजोड़ करना शामिल ताकि ईको फ्रेंडली व यूजर फ्रेंडली कपड़ों को ईजाद किया जा सके। इसके प्रचार-प्रसार के लिए ई-मार्केटिंग का भी सहारा लिया जा रहा है। जाहीर है संभावनाएं असीम हैं। उल्लेखनीय है कि खादी एवं ग्रामोद्योग के उत्पादों को बेचने के लिए लगभग 7000 शोरूम उपलब्ध हैं। गिरिराज सिंह का मानना है कि पर्यावरण के अनुकूल नए तकनीकों व मार्केटिंग युक्तियों का इस्तेमाल कर खादी उद्योग का कायाकल्प किया जा सकता है।

साभार: न्यूज भारती

रेल बजट में खादी क्षेत्र से भी सहयोग लेने पर जोर

संसद में वर्ष 2016-17 का रेल बजट प्रस्तुत करते हुए रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने खादी क्षेत्र का भी ध्यान रखा है। उन्होंने अपने रेल बजट संबोधन में कहा कि 'हमने रोजगार के सृजन में सहायता करने और ग्रामीण भारत में आत्मनिर्भरता लाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के साथ भागीदारी की है, जिसके परिणामस्वरूप 17 लाख श्रम दिवस का रोजगार उपलब्ध होगा। हम यात्रियों के लिए उत्पाद तैयार करने तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए उनके साथ निरंतर भागीदारी करेंगे और भारतीय रेलवे के विशाल संसाधनों तथा परिसम्पति का इस्तेमाल करके उनका विपणन भी करेंगे। हम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों से उत्पादों के स्रोत को प्रात्साहित करेंगे।"

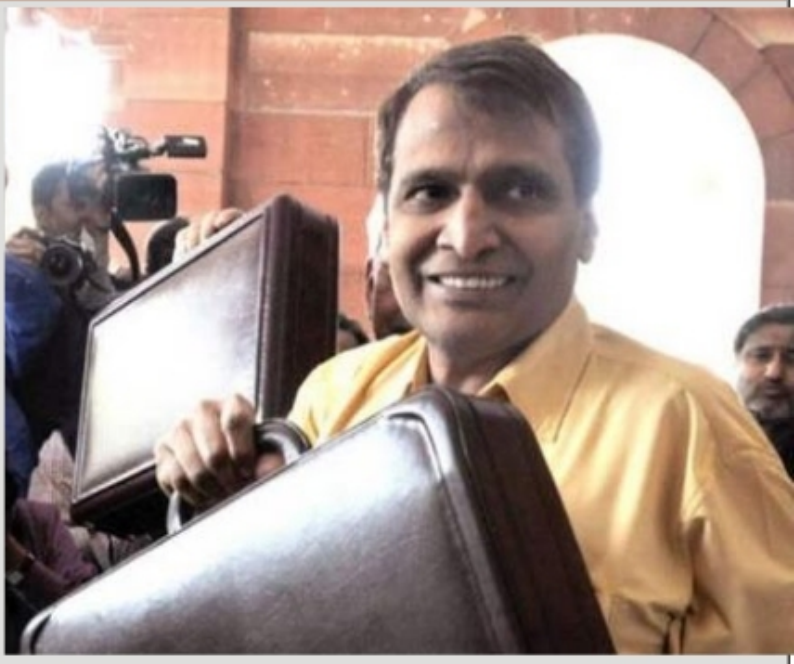

खादी में नजर आएंगे महाराष्ट्र राज्य के होमगार्ड, खरीदे जाएंगे 54 लाख के खादी वस्त्र

मुंबई, 17 फरवरी 2016: खादी का नेताओं से पुराना नाता है। अब मोदी सरकार खादी को आम वस्त्र बनाना चाहती है। खादी के लिए नए-नए बाजार खोजे जा रहे हैं।

इसी के मद्देनजर अब पुलिसकर्मी भी खादी की खाकी पहने नजर आएंगे। राज्य का होमगार्ड विभाग अपने जवानों के लिए खादी खाकी कपड़ा खरीदने जा रहा है। जबकि दिल्ली सहित कई राज्यों ने अपने पुलिसकर्मियों के लिए खादी के कपड़े खरीदे हैं।

महाराष्ट्र पुलिस से भी खादी व ग्रामोद्योग विभाग सम्पर्क में है। केन्द्र में मोदी सरकार आने के बाद खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने खादी कपड़ों का बाजार बढ़ाने पर खास जोर दे रही है। प्रधानमंत्री अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में भी लोगों से खादी के कपड़े पहनने की अपील कर चुके हैं।

आयोग मुख्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि खादी का बाजार बढ़ाने के लिए हम सरकारी महकमों से सम्पर्क कर रहे हैं। महाराष्ट्र का होमगार्ड विभाग सालाना 54 लाख रुपए का खाकी कपड़ा होमगार्ड के कर्मचारियों के लिए खरीदता है। राज्य में 38 हजार होमगार्ड के जवान हैं। विभाग की तरफ से हर साल इनको वर्दी के लिए कपड़ा दिया जाता है। खादी व ग्रामोद्योग आयोग की पहल पर इस पर होमगार्ड विभाग वर्दी के लिए खादी कपड़े खरीदने पर विचार कर रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस से भी खादी ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारी सम्पर्क करेंगे।

पोर्ट ब्लेयर में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन

वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तीसरे बैच का आयोजन भारतीय स्टेट बैंक आर-एसईटीआई, मोहनपुर, पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के. एस. राव ने कार्यक्रम का उदघाटन किया।

इस कार्यक्रम में अंडमान निकोबार प्रशासन के उद्योग निदेशक श्री एम. एन. मुरली, आयोग के उप मुख्य कार्यक्रम अधिकारी (ग्रामोद्योग/क्षमता विकास) श्री वाय. के. बारामतिकर, अर्थ अनुसंधान निदेशालय के निदेशक प्रभारी श्री जे.एम. राव तथा भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री आलोक कुमार सिन्हा, अंडमान राज्य सहकारी बैंक के प्रबंधक निदेशक श्री रविन्द्र राव, जिला उद्योग केंद्र के प्रबन्धक(ऋण) श्री गौतम मण्डल एंव अन्य अतिथि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में, कमबेल बे से डिग्लीपुर तक क्षेत्र के 47 भागार्थियों ने भाग लिया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के. एस. राव ने प्रत्येक भागार्थी से संबंधित विषय पर विचार-विमर्श किया और उनकी परियोजनाओं की सराहना की तथा संबन्धित क्षेत्र में विकास के संभावनाओं के बारे में भी जानकारी दी तथा उन्होंने, उद्योग का निरंतर विकास करने इसे मार्केटभिमुखी बनाने और स्थायी बनाने हेतु सुझाव दिये। श्री राव ने, आयोग के प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के माध्यम से सम्पूर्ण संघशासित प्रदेश में सूक्ष्म उद्यमों का विस्तार करने के लिए आयोग की प्रतिज्ञा को पुन: दोहराया तथा कहा कि इस कार्यक्रम में अधिकतम युवा बेरोजगारों को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार के सहयोग से अंडमान निकोबार का आर्थिक रूप में विकास करने के लिए युवाओं का असीम योगदान होगा।

श्री वाई. के. बारामतिकर ने अपने सम्बोधन में सूचित किया कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत अभ्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में आर-एसईटीआई के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किये है और समझौता के तहत प्रशिक्षणार्थिओं को इस योजना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। आर-एसईटीआई द्वारा दो वर्ष के लिए प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इकाईयां राज्य स्तरीय संघ के स्वरूप में होनी चाहिए ताकि वे नेटवर्किंग के रूप में कार्य कर सके और एक दूसरे को सहयोग दे सके। इससे पहले, अंडमान और निकोबार के कार्यकारी अधिकारी श्री ए, सिन्हा रॉय ने अपने स्वागत संबोधन में कार्यक्रम में आये सभी भागर्थियों का स्वागत किया तथा संघशासित राज्य में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रगति की रूपरेखा प्रस्तुत की। एसबीआई आर-एसईटीआई के निदेशक श्री गौतम चक्रवर्ती धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

बंगलुरू में हिंदी कार्यशाला आयोजित

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, बेंगलूर के सभा-कक्ष में दिनांक 16.02.2016 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता श्री एम. जगन्नाध राव, राज्य निदेशक महोदय ने की। कार्यशाला का विषय "वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यांक के अनुरूप हिंदी में कार्यालयीन कार्य" रखा गया था।

कार्यशाला में सत्र-संचालन हेतु श्री विजय कुमार, सहायक निदेशक(राजभाषा), केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूर को विशेष वक्ता के रूप आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला में आंचलिक कार्यालय एवं राज्य कार्यालय, बेंगलूर के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला के प्रथम चरण में, वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोजिताओं के विजेताओं और हिंदी में अच्छे कार्य के लिए कर्मचारियों को अध्यक्ष महोदय एवं वक्ता महोदय द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया।

अपने अध्यक्षीय भाषण में राज्य निदेशक महोदय ने कहा कि हमें मिलजुल कर राजभाषा संबंधी वार्षिक कार्यक्रमों के अनुरूप कार्यालय कार्य करना चाहिए। साथ ही विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने सभी पुरस्कार विजताओं को बधाई दी और अधिकाधिक कार्यालय कार्य हिंदी में करने का अनुरोध किया।

कार्यशाला के दूसरे चरण में, वक्ता श्री विजय कुमार, सहायक निदेशक(राजभाषा), केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूर ने राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों एवं कर्मचारियों के संवैधानिक दायित्वों का जिक्र किया। उन्होंने उक्त दोनों में ताल-मेल बैठते हुए कार्यालय कार्य को सहज ढंग से करने के बारे में विस्तार से बताया। अपनी भाषा और अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए हमें अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को हिंदी में मिलाना होगा।

उन्होंने कहा कि अन्य भारतीय भाषाओं जैसे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि में संस्कृत से लिए गए शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखना चाहिए। इससे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ एक संयुक्त परिवार की तरह विकसित होंगी। प्रतिभागियों के पूछे गए सवालों का सहज रूप में समाधान किया गया।

श्रीमती वी.एल. कल्पना, आशुलिपिक(हिंदी) ने धन्यवाद ज्ञपित किया।

■■■

एन.आई.एफ.टी. के छात्रों ने खादी उत्पादन संबंधी गतिविधियों को देखा

एन.आई.एफ.टी. के छात्रों एक दल ने अहमदाबाद के रणपुर स्थित भाल नलकांठा खादी ग्रामोद्योग मण्डल का दौरा किया तथा उत्सुकतापूर्ण खादी उत्पादन संबंधी गतिविधियों का अवलोकन किया, जहां मण्डल के सचिव श्री गोविन्द धावी ने उन्हें संपूर्ण वूल खादी उत्पाद संबंधित गतिविधियों की जानकारी प्रदान की।

सेवानिवृत्ति

दिनांक 31 जनवरी, 2016 को आयोग के राज्य कार्यालय, अहमदाबाद में कार्यरत आशुलिपिक श्रीमती वत्सला राजन आयोग के सेवा से सेवानिवृत्त हुईं। वे, वर्ष 1983 में आयोग में आशुलिपिक के रूप में नियुक्त हुई थी। उनकी सेवानिवृत्ति पर राज्य कार्यालय, अहमदाबाद में एक सत्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां आयोग के निदेशक श्री संजय जी. हेडाऊ ने शॉल उठाकर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर श्री श्रीमती वत्सला राजन का सत्कार किया।

इस अवसर पर कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने श्रीमती वत्सला राजन को सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें स्वस्थ और उत्तम जीवन की शुभकामनाएं दीं।

छत्तीसगढ़ में निजी स्कूल के नन्हे-मुन्ने पहनेंगे खादी

रायपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते थे कि हिंदुस्तान की अहिंसा और आजादी खादी में है। भावी पीढ़ी इन्हीं बातों को समझ सके, कुछ इसी मकसद से छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड शहर के बड़े स्कूलों में जाकर खादी की एक ड्रेस खरीदने के लिए प्रस्ताव रखेगा, ताकि इन स्कूलों के नन्हे बच्चे खादी की ड्रेस पहनकर स्वच्छ विचार और स्वच्छ भारत का संदेश दे सकें। इसके अलावा खादी बुनने वाले बुनकर भी इन बच्चों को स्कूलों में जाकर खादी की खूबियां गिनाएंगे।

खादी कपड़ों के प्रचार-प्रसार के लिए बोर्ड हरसंभव प्रयास कर रही है। इस कड़ी में शहर के दर्जनभर से ज्यादा निजी स्कूलों का चिन्हांकन किया जा रहा है, जहां की मैनेजमेंट खादी की खरीदी कर सके। शहर के दो बड़े स्कूलों में इस विषय पर चर्चा हो गई है। अन्य स्कूलों का दौरा महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा, ताकि अगले सत्र से खादी ड्रेस का उपयोग ये बच्चे कर सकें।

बुनकर बताएंगे खादी नो पॉल्यूशन

खादी वस्त्र के निर्माण में एक प्रतिशत भी पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता, जबकि अन्य वस्त्र जैसे सिल्क और पॉपलीन को बनाने का काम बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां करती हैं, जिससे धुआं निकलता है और पर्यवारण काफी प्रदूषित होता है। बिजली की खपत भी भारी मात्रा में होती है। इसके अलावा खादी पहनने से ग्रामीण व कृषि से जुड़े लोगों की आमदानी बढ़ेगी। इन स्कूलों में जाकर बुनकर बताएंगे कि खादी कैसे बनाई जाती है, क्यों उपयोग करे और इससे आने वाली पीढ़ी और समाज पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

एक खादी ड्रेस अनिवार्य करे सरकार

बोर्ड द्वारा खादी में दिए जाने वाले 20 प्रतिशत छूट की राशि को अनुदान के रूप में राज्य सरकार पेमेंट करती है, लेकिन राज्य सरकार ही अब तक अपने कर्मचारियों को खादी की एक ड्रेस खरीदने के लिए आदेश नहीं दिया है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने खादी को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली में पुलिस अधिकारी-कर्मचारी भी खादी वत्र खरीदे हैं। अगर छत्तीसगढ़ सरकार भी अधिकारी-कर्मचारी को एक जोड़ी खादी की ड्रेस खरीदने को अनिवार्य कर दे तो बोर्ड की बिक्री में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो जाएगी।

निजी स्कूलों के बच्चों के पास एक खादी वस्त्र अनिवार्य हो, इसलिए बोर्ड स्कूलों में जाकर प्रस्ताव रख रही है। इससे बच्चों के मन में खादी के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। बुनकरों को भी स्कूलों में ले जाएंगे, जहां ये खादी की खूबियां बच्चों को बताएंगे।

-आलोक कटियार, एमडी, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने दिनांक 16-18 फरवरी, 2016 को माननीय सांसद श्री के.सी.त्यागी के नेतृत्व में अण्डमान निकोबार संघशासित प्रदेश का दौरा किया। विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक की झलकियां

श्री के.के.जालान ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करने के पश्चात पहली बार दिनांक 11 फरवरी, 2016 को आयोग मुख्यालय का दौरा किया तथा आयोग के कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक की झलकियां

आयोग ने भारतीय विज्ञान काँग्रेस में भाग लिया

"इण्डियन साइंस कांग्रेस-प्राइड ऑफ इण्डिया एक्स्पो 2016" मैसूर विश्वविद्यालय में सम्पन्न

मैसूर विश्वविद्यालय में 3 जनवरी से 7 जनवरी 2016 तक 103वी भारतीय विज्ञान काँग्रेस में भारत में स्वदेशी विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत एक्सपो 2016 का आयोजन किया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस एक्सपो में भाग लिया। इस एक्सपो में आयोग के राज्य कार्यालय, चेन्नई, से 8-तकुए का सोलर चरखा और केन्द्रीय ताडगुड एवं ताड उत्पाद संस्थान , माधवरम,चेन्नई से ताड़ उत्पाद एंव सीबीआरटीआई , पुणे से मधुमक्खीपालन तथा शहद उत्पादों पर संग्रहित एक प्रदर्शनी आयोजित की गयी।

इस एक्स्पो में 131 प्रतिभागियों में कई प्रतिष्ठित संगठनों/अनुसंधान संस्थानों/विश्व विद्यालयों इत्यादि ने भाग लिया। माननीय प्रधान मंत्री ने 3 जनवरी 2016 को 103वीं भारतीय विज्ञान काँग्रेस का उदघाटन किया था।

4 जनवरी 2016 को 103वी भारतीय विज्ञान काँग्रेस में, जेनेसिस-XIV, सेम्पोस्यिम के तहत स्वदेशी विकास के माध्यम से "मेक इन इंडिया मिशन" - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भूमिका पर एक संगोष्ठी का आयोजन हयूमीनिटिस ब्लॉक औडिटोरियम, मैसूर विश्व विद्यालय में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ने की। इस सत्र में उच्चाधिकार प्राप्त पैनल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के नीतियों, योजनाओं के बारे में चर्चा की गई और सफल उद्यमियों के सफलता की कहानियों, अनुसंधान और विकास केन्द्रों द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास कार्यों एंव बी2जी के स्टार्टप हेतु पर्यावरण-अनुकूल व्यवस्था का निर्माण तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पर संवाद एवं मॉनिटरिंग पर भी विचार-विमर्श किया गया।

एक्स्पो में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के स्टॉल में सोलर चरखा, के अतिरिक्त ताड़ उत्पादों और मधुमक्खीपालन के प्रदर्शन को भी प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। विद्यमान न्यू मॉडल 8-तकुआ चरखे में सोलर पावर पैनल्स, रेग्युलेटर्स, बैटरी , इन्वरटर्स, और मोटर्स के साथ सोलर चरखे के रूप में प्रदर्शनी में रखा गया और इसके उपयोग में लाने के संबंध में लोगों को जानकारी दी गयी। इस प्रदर्शनी में भारतीय विज्ञान काँग्रेस के प्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी आगंतुक के रूप में उपस्थित थे। आगंतुकों और प्रतिनिधियों ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के स्टॉल का अवलोकन किया और उन्होंने सोलर ऊर्जा से परिचालित सूत चरखा के मॉडल की सराहना की ।

महिला सशक्तिकरण का माध्यम बना सोलर चरखा

-पुष्पमित्र

पिछले दिनों 14वें वित्त आयोग की टीम झारखंड की वित्तीय जरूरतों का आकलन करने के लिए रांची आयी हुई थी। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से उन्हें रांची से पिस्का नगड़ी इलाके का भ्रमण कराया गया जहां वे उन महिलाओं से मिले जो सोलर चरखा की मदद से सिल्क का धागा तैयार कर रही हैं और इस प्रयास के जरिये ये महिलाएं अपने परिवार और गांव में खुशहाली ला रही हैं। जब वित्त आयोग की टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि झारक्राफ्ट द्वारा बनाये गये कॉमन फेसिलिटी सेंटर में ये महिलाएं तरह-तरह के चरखों की मदद से कोकून से रेशम धागा तैयार करने में जुटी हैं और इन मशीनों ने महिलाओं की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता में बड़ा फर्क ला दिया है।

बरसों से धागा बनाती हैं महिलाएं

दरअसल झारखंड में अर्जुन पेड़ पर पलने वाले रेशम कीट से तसर धागा तैयार करने का काम महिलाएं बरसों से करती रही हैं। मगर ज्यादातर महिलाएं यह काम बिना किसी उपकरण की मदद से करती थीं या बहुत हुआ तो लकड़ी की तकली या चरखे का इस्तेमाल कर लिया। इससे वे एक दिन में बहुत कम धागा तैयार कर पाती थीं और धागे की गुणवत्ता भी बहुत बेहतर नहीं होती थी।

ऐसे तैयार हुई मशीन

इस समस्या का समाधान निकालने के क्रम में पहले रीलिंग मशीन गढ़ी गयी और बाद में उसे सोलर उपकरणों से जोड़कर ऐसा बनाया गया कि गरीब महिलाएं बहुत कम खर्च में इसका इस्तेमाल कर सकें। झारक्राफ्ट से मिली जानकारी के मुताबिक पहले वे सीएसटीआरआइ बेंगलुरू द्वारा तैयार स्पिनिंग और रीलिंग मशीन का इस्तेमाल किया करते थे। मगर उस मशीन की उत्पादकता काफी कम थी और एक महिला दिन भर काम करने के बाद बमुश्किल 50 रुपये कमा पाती थीं. बाद में उन्होंने महसूस किया कि हिंद मशीनरी, भागलपुर द्वारा तैयार स्पिनिंग मशीन ज्यादा बेहतर नतीजे दे रही है। इससे प्रति व्यक्ति उत्पादकता में काफी फर्क आ जाता है। हालांकि सीएसआरचीआइ की मशीन से तैयार धागे की गुणवत्ता बेहतरीन थी मगर उसकी उत्पादकता काफी कम थी, जो एक महिला के मेहनताने के लिए अपर्याप्त हो रहा था।

सोलर कंपनी से गंठजोड़

इन तमाम मशीनों के अनुभवों का सहारा लेते हुए झारक्राफ्ट ने सेंट्रल सिल्क बोर्ड और एनर्जी रिसोर्सेज नामक दिल्ली की एक सोलर कंपनी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। इस साझा प्रयास के जरिये सोलर पावर्ड कॉमपैक्ट रीलिंग मशीन- समृद्धि को तैयार किया। बाद में समृद्धि के नाम से झारक्राफ्ट और सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने इसका पेटेंट भी कराया। इस मशीन से एक ओर जहां उत्पादकता बढ़ी वहीं उत्पादित रेशम धागे की गुणवत्ता में भी सुधार आया। झारक्राफ्ट के जीएम ऑपरेशन डॉ. बी.सी. प्रसाद बताते हैं कि अब इस मशीन की सहायता से महिलाएं एक दिन में 200 ग्राम तसर धागा तैयार कर सकती हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें एक रुपये प्रति ग्राम की दर से दो सौ रुपये रोजाना की आमदनी हो सकती है। हालांकि पर्याप्त अभ्यास नहीं होने के

कारण कई महिलाएं 150 ग्राम धागा ही तैयार कर पा रही हैं, मगर फिर भी उनकी रोज की आमदनी 150 रुपये की हो जा रही है।

खरसावां में पहला प्रयोग

झारक्राफ्ट की ओर से सबसे पहले खरसावां में इस मशीन का इस्तेमाल किया गया. वहां की महिलाओं ने इसका सफलता पूर्वक संचालन कर साबित कर दिया कि यह मशीन उनकी किस्मत को बदल सकता है. फिर धीरे-धीरे झारखंड के कई इलाकों में महिलाओं को इस मशीन पर काम करने का मौका दिया गया। फिलहाल झारखंड में ऐसी 4000 मशीनें काम कर रही हैं, जो खरसावां, देवघर, बेंगाबाद और रांची के कई सेंटर में संचालित हो रही हैं। इस मशीन में एक मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी जोड़ा गया है ताकि महिलाएं अपना मोबाइल चार्ज कर सकें साथ ही एक बल्ब भी लगाया गया है जिससे वे रात में भी धागा तैयार कर सकती हैं।

रांची से सटे पिस्का नगड़ी इलाके में महिलाओं को जोड़कर एक अस्थायी भवन में कॉमन फेसिलिटी सेंटर खोला गया और स्पिनिंग इकाई की शुरुआत की गयी। बाद में इस इकाई के लिए स्थायी भवन का निर्माण कराया गया और समृद्ध मशीनें लगायी गयीं।

4-5 हजार प्रति माह की आय

इन मशीनों के लगने से यहां की 30 महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है. 2009 से लेकर अब तक इस इकाई ने 121.56 लाख रुपये का रेशम धागा उत्पादित कर कुल 26.18 लाख का लाभ अर्जित किया है. पिछले दो सालों से ये महिलाएं सामान्यतरू 8 से 9 लाख रुपये सालाना का लाभ अर्जित कर रही हैं। यहां कुछ महिलाएं आंशिक रूप से काम करती हैं और कुछ पूर्णकालिक काम करने वाली महिलाएं औसतन 4 से 5 हजार रुपये प्रति माह की आय अर्जित कर रही हैं।

इनमें से एक महिला मंजू उरांव को दो बार राज्य सरकार द्वारा उनके काम को देखते हुए पुरस्कृत किया गया है जबकि मंगरी उरांव को एक बार राज्य सरकार की ओर से प्रथम पुरस्कार मिला है। निस्संदेह उनके जीवन में आयी इस समृद्धि में सोलर चरखा समृद्धि का बड़ा योगदान है।

अपनी सुविधा से करती हैं काम

डॉ. प्रसाद कहते हैं कि इस मशीन की कीमत 26 हजार रुपये के आसपास पड़ती है। जबकि सेंट्रल सिल्क बोर्ड की रीलिंग मशीन 22 हजार रुपये में आती थी। इस हिसाब से यह मशीन महिलाओं के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। वे बताते हैं कि घर के पास रीलिंग सेंटर होने के कारण महिलाओं को काफी सुविधा रहती है। वे घर का काम करते हुए इस काम को करती हैं। अधिकांश महिलाएं सुबह 6 से 8 काम करती हैं फिर घर जाकर घर का काम निबटाती हैं. फिर से 12 से 4 बजे तक काम करती हैं इसके बाद 5 से 6 बजे तक एक घंटा काम कर लेती हैं।

आत्म निर्भरता बढ़ी

वे बताते हैं कि इससे महिलाओं की आत्म निर्भरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार सेंटर में कुछ पुरुष जो संभवत: इन महिलाओं के पति थे आये और उन्होंने कहा कि चलो धान के खेत में काम करना है। इस पर महिलाओं ने उन्हें अपने पास से 50 रुपये निकाल कर दिये और कहा कि जाओ किसी और मजदूर से करवा लो। यहां हम इतनी कमायी छोड़कर नहीं जायेंगे।

साभार: प्रभात खबर

बेरोजगार महिलाओं के लिए KVIC की नई पहल

■ युवाओ में लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है यह पायलेट प्रोजेक्ट है। कताई और बुनाई के इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 30 युवा महिलाओं को रोजगार प्रदान करेगा खादी ग्रामोद्योग

-वी के सक्सेना, चेयरमैन KVIC

वाराणसी, लोकसत्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के जिस गाँव जयापुर को गोद लिया हुआ है। उस जयापुर गांव में खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा वाराणसी की बेरोजगार युवा महिलाओ को रोजगार प्रदान करने के लिए आयोग द्वारा 25 चरखे और 5 करघे स्थापित किये गए। खादी ग्राम उद्योग द्वारा जयापुर वाराणसी में यह पायलेट प्रोजेक्ट युवाओ में लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।

खादी और ग्राम उद्योग के अध्यक्ष वी के सक्सेना ने आज जयापुर वाराणसी का दौरा किया और महिला ग्राम प्रधान श्रीमती दुर्गा देवी से मुलाकात की। इस अवसर पर सक्सेना ने घोषणा की कि खादी ग्रामोद्योग कताई और बुनाई के इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 30 युवा महिलाओं को रोजगार प्रदान करेगा। सक्सेना ने ग्राम प्रधान श्रीमती दुर्गा देवी से बेरोजगार महिलाओ की सूची की भी मांग की जिससे उन्हें शीघ्र अति शीघ्र उनका प्रशिक्षण प्रारम्भ हो सके और रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। अहमदाबाद में निर्मित प्रयोग समिति द्वारा इन चरखो और करघो का निर्माण किया गया है और यह अहमदाबाद की NGO National Council for Civil Liberties ने दान करे है।

ग्रामोद्योग के अध्यक्ष श्री.वी. के सक्सेना ने बताया की प्रधानमंत्री द्वारा गोद लिए गए इस गाँव जयापुर में यह पायलेट प्रोजेक्ट सफल होने पर गाँव में 200 चरखो और 50 करघो का बड़ा प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा जिससे वारणसी के जयापुर की करीब 250 युवा बेरोजगार महिलाओ को रोजगार मिल सके।

KVIC Chairman: Khadi is the most eco-friendly cloth

…naugurating the sales outlet and an exclusive exhibition o… …hadi and Village industries products in the Consumer Sto… …aykar Bhavan, Marine Lines, V. K. Saxena, Chairman, KVIC s… …hat this a new beginning in the history of KVIC in the form… …e-up with Income Tax Department. A zero carbon foot pr… …hadi, is the most eco-friendly cloth, he added. KVIC is …enerating employment for the 12.5 lakh persons and sal… …. 37642.24 crs. Devendra Saksena, Principal Chief …ommissioner, Income Tax speaking on the occasion was … support the cause of employment generation for the 1… …kh persons affiliated with Khadi and VI sector. Arun Kum… …EO, KVIC reiterated that Khadi is a heritage cloth and mo… …itable for Mumbai city. K.S. Rao, Dy. CEO, KVIC welcome … …gnitaries and introduced about Khadi and its quality.

लगातार बढ़ रही खादी की मांग

37642.24 करोड़ पहुंचा कारोबार

[illegible] मुंबई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की … के बाद खादी वस्त्रों की … में लगातार इजाफा हो रहा है. वर्ष 2015 में खादी का कारोबार बढ़कर 37642.24 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. मुंबई में बढ़ती खादी की … की आपूर्ति के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने आयकर … के कन्ज्यूमर स्टोर से … उत्पादों की बिक्री आरंभ … दी है, जिसका उद्घाटन … को केवीआईसी के … वी.के. सक्सेना एवं … टैक्स विभाग के … चीफ कमिश्नर देवेन्द्र … ने किया.

मेक इन इंडिया मुहिम मेक इन विलेज के मार्ग से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकती है. देश के छोटे-छोटे गांवों में तैयार खादी उत्पादों की बढ़ी बिक्री से यह सिद्ध हो गया है. मेक इन इंडिया मुहिम कामयाबी के पथ पर तेजी से अग्रसर है. खादी विश्व के सबसे उत्कृष्ट कपड़ों की श्रेणी में आता है. इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. हर उम्र का नागरिक इसे धारण कर सकता है.

वी.के. सक्सेना, चेयरमैन, केवीआईसी

1 करोड़ को रोजगार

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आने वाले समय में 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है. मौजूदा समय में आयोग 15 लाख कारीगरों को रोजगार दे रहा है. केवीआईसी के सीईओ ए. के. झा के मुताबिक रोजगार के साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए आयोग द्वारा एक साल के भीतर कारीगरों को 2 हजार सोलर चरखा उपलब्ध करवाए जाएंगे.

फ्रेंचाइजी बढ़ाने योजना

खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए केवीआईसी द्वारा विभिन्न मार्केटिंग पहल की गई है. विभिन्न स्थानों पर खादी की उपलब्धता में बढ़ोतरी एवं खादी ग्राम उद्योग के संचितरण में वृद्धि करने के उद्देश्य से 15 प्रमुख शहरों में फ्रेंचाइजी योजना प्रारंभ की जा रही है. इसके अलावा सरकारी आपूर्ति में वृद्धि करने और थोक बिक्री करने हेतु हेल्पलाइन प्रारंभ करने का भी प्रयास किया जा रहा है.

करोड़ों के ऑर्डर

वी.के. सक्सेना के अनुसार, प्रधानमंत्री के आवाहन के बाद से देश के सरकारी संस्थानों ने खादी का उपयोग करना आरंभ कर दिया है. इसके तहत हवाई कंपनी एयर इंडिया से 125 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त हुआ है.

खादी ग्रामोद्योग के साथ साझेदारी

प्रभु ने कहा कि खादी ग्रामोद्योग के साथ साझेदारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों मे 17 लाख श्रम दिवस सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि रोजगार के साथ ही भारतीय रेल हर साल इंजीनियरिंग और एमबीए के 100 छात्रों को दो से छह महीने की इंटर्नशिप कराएगी। प्रभु ने कहा कि रेल के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने को सरकार विभिन्न टूरिस्ट सर्किट के लिए ट्रेन चलाने की संभावनाएं भी तलाशेगी।

लोकसत्य

दिल्ली, उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड से प्रकाशित — सत्य के संग, असत्य से जंग

वर्ष 01, अंक : 200 | www.epaper.loksatya.com | सोमवार, 1 फरवरी 2016 | मूल्य : 3.00 | कुल पृष्ठ : 12

'मन की बात' खादी के जरिए भारतवासियों को स्वावलंबी बनाने के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को आगे बढ़ा रही सरकार

करोड़ों लोगों को रोजगार देने में सक्षम खादी : मोदी

सरदार पटेल कहा करते थे, हिन्दुस्तान की आजादी, अहिंसा, किसान का कल्याण सिर्फ खादी में ही है। आज खादी एक अलग पहचान बन गया है। यह युवा पीढ़ी के लिए फैशन का नया ट्रेंड सेट कर रहा है। खादी का पहले सरकारी इस्तेमाल खूब होता था, पर अब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोग बेरोजगार होते गए। पर डाक विभाग, रेलवे, जैसे कई विभाग ने खादी को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। खादी में बड़ी ताकत है। ये 18 मानव दिन का रोजगार खड़ा करेगा।

नई दिल्ली, लोकसत्य

[illegible]

-शेष पृष्ठ 7 पर

भारत में हम रोजगार सृजन करते हैं तथा समृद्धि बुनते हैं

खादी न्यूज

मार्च 2016

LIFEST

Style extravaganza at annual fashion show

Woven Edge

The School Of Fashion Technology (SOFT), located at Narhe Ambegaon in Pune, is one of the premier fashion institutes in the country, and recently held its convocation ceremony and annual fashion show.

Over 124 students displayed their talent and expertise attained throughout their journey at the institute, showcasing a collection based on khadi and handloom for the youth. Prominent Indian and international designers along with Meher Castelino, judged the collection and provided students with their expert opinion in the field of fashion. The occasion was graced with the presence of guests including Rahul Mehta, president, of International Apparel Federation. Also in attendance were the president, chairman, vice-chairman and secretary of the Maharshi Karve Stree Shikshan Samstha.

The collections which won awards included Woven Edge (Best Design Collection), Sorted Entanglement (Most Commercially Viable Collection), Ribbon Around The Bomb (Best Surface Treatment) and From The Heart of The Ocean and Play School (Mentor's Awards).

Ribbon Around the Bomb

Sorted Entanglement

New players give khadi a run for its money

During his last *Mann Ki Baat*, PM had made a strong plea for popularisation of khadi

PARTHA SARATHI BISWAS
PUNE, FEBRUARY 13

PRIME MINISTER Narendra Modi, during his last *Mann Ki Baat*, had made a strong plea for popularisation of khadi. But the fabric is now facing a threat in cities like Pune with the arrival of competitors that are eating into its market share.

Located in the commercial hub of Laxmi Road is the Gandhi Khadi Bhandar, one of the oldest shops dealing in the fabric. However, senior management members here say that although they have a set clientele, the footfall of the younger generation is less.

A second shop that opened off Karve Nagar nearly a year ago is now selling mixed fabrics like semi-khadi or mixed khadi. One of the major drawbacks of pure khadi, the management says, is that its colour fades away after washing. The newer mixed fabrics do not face this problem. "We make it a point to let the customers know that what they are buying is not 100 per cent khadi," says a senior management member of the shop.

He, however, says there has been no new rush of customers after the Prime Minister's *Mann Ki Baat*.

Management members of khadi shops say the biggest roadblock was the uncertainty of weavers. "The government should ensure weavers get paid. Otherwise, khadi will not survive. Already there are signs that the next generation might not go for khadi," they said.

As per records of Khadi and Village Industries Commission (KVIC), the annual turnover the khadi market in the country is more than Rs 500 crore.

While the government-run khadi stores mostly have a dark and dreary look about them, the newly opened Khadi Gramodyog Bhavan, the flagship store at Shivajinagar, has a different look and feel about it. Located within the premises of the Central Bee Research Institute, this shop is run by Burdwan Rural Khadi Gramodyog Samity, a trust working directly with weavers and spinners of Burdwan district in West Bengal.

Nisha Mukherjee from the Samity says this is their second flagship store in the country after Delhi. "We want to showcase and sell genuine khadi. Through our mother trust, Natraj Khadi Silpa Samity, we have been involved in khadi for more than 30 years," she says.

In the past, the Samity has been involved only in the business of fabrics and this is the first time they have entered the garment market. The demand for khadi fabric, Mukherjee says, is high in countries like Japan and Israel. The trust deals with around 60 weavers and 95 spinners. Maharashtra is one of the states with a high demand for khadi.

Natraj Khadi Silpa Samity is a directly aided unit of KVIC. Dilip Mukherjee, one of its trust members, says while the raw material is sourced from the government, weavers and spinners produce the fabric. Tailors at the Khadi Bhavan in Mumbai fashion the garment and in tandem with the revamp plan of khadi, newer designs and colours are used in the garments.

Mukherjee says while the younger generation is interested in khadi, there needs to be a change in the mentality among the stakeholders. "The decision of the government to allow quality-wise procurement has ensured quality of the fabric. We now need to change the mentality of doing business," he said.

A flagship store of Khadi Gramodyog Bhavan at Shivajinagar. Dipesh Salve

Sales outlet opening

An Industries Commission sales outlet is going to be inaugurated on Wednesday at the Consumer Stores at Aykar Bhavan as part of the KVIC's efforts to promote the sale of khadi and support rural artisans.

...ूर में हमारे होनहार 'किस्सा भरत मिलाप' देखें P5

फरीदाबाद

सेक्टर-12 स्थित हुडा मैदान में राज्यस्तरीय खादी ग्राम उद्योग के सौजन्य से लगाई गई प्रदर्शनी में मंगलवार शाम फैशन शो आयोजित किया गया। रैंप पर बच्चों ने खादी के कपड़े प्रदर्शित किए

यूथ को भा गया खादी का न्यू लुक

सेक्टर-12 स्थित खेल परिसर के पास खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी

■ एनबीटी न्यूज, सेक्टर-12

प्रदर्शनी में जैकेट और कुर्तियों के अच्छे डिजाइन दिखे

आएगा सौर ऊर्जा से चलने वाला चरखा

खादी के ये हैं टॉप फैशन प्रोडक्ट

जींस का रहा क्रेज

खादी की शर्ट के अलावा जींस भी लोगों ने प्रदर्शनी में देखी

रैंप पर उतरे बुनकर और बच्चे

■ एनबीटी न्यूज, फरीदाबाद

'स्कूल ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी'च्या विद्यार्थ्यांचा खादी व हातमागामधील फॅशन शो

डिझाइन कलेक्शन - वोव्हन एज

बेस्ट सरफेस ट्रिटमेंट - रिबन अराऊंड द बॉम्ब

मोस्ट कमर्शिअली व्हायबल कलेक्शन - सॉर्टेड एन्टॅंगलमेंट

बेस्ट डिझाइन कलेक्शन - वोव्हन एज

बेस्ट सरफेस ट्रिटमेंट - रिबन अराऊंड द बॉम्ब

भारत में हम रोजगार सृजन करते हैं तथा समृद्धि बुनते हैं

INDIAN EXPRESS

Women form 82% of Khadi work force

Centre-state drive to promote khadi saw 15 new outlets being opened in city

EXPRESS NEWS SERVICE
MUMBAI, FEBRUARY 10

One khadi outlet has been launched at the Income Tax head office at Marine Lines to generate awareness among people

THE KHADI and Village Industries Commission is promoting khadi in a big way and targeting to employ one crore people in this sector in the next four years. The plan has already gathered momentum in commercial capital Mumbai, where at least 15 new khadi outlets have been launched including one at the Income Tax head office at Marine Lines to generate awareness among people and help village weavers earn more.

KVIC chairman Vinai Kumar Saxena said, "The industry with a turnover of Rs 33,000 crore has great potential and would help serve weavers in rural India."

Prime Minister Narendra Modi has taken up the initiative to revive "khadi" clothes and products which are eco-friendly and part of the centre-state mission to promote cottage and village industries. Of 12.5 lakh individuals employed in the khadi industry, 82 per cent are women.

He revealed, "The Indian

the main centre where centre-state can work to take "khadi" clothes and products to people. Principal Chief Income Tax Commissioner Devendra Saxena said, "We have given our own outlet in our IT office for khadi products as we believe it would help in generating greater employment." Unlike in the past, when khadi was tagged as clothes confined to politicians, it is evolving to be more affordable, and also comfortable as a designer wear in various colours.

Forever News

Wednesday, 10 February 2016 20:29

KVIC to promote their product through newly launched franchise scheme

Hon'ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi had given a clarion call through "Man Ki Baat" to buy atleast one item of Khadi to support the rural artisans of our Country. The Hon'ble Prime Minister had also appreciated the initiative taken by few Govt. Departments/agencies like Post and Telegraph Departments, Uttarakhand, Police etc for providing marketing support to Khadi. Various marketing initiatives have been taken up by KVIC to promote Khadi & Village Industries Products in the Country. The franchise scheme is being launched in 15 major cities and towns to extend the availability of Khadi in different locations and increase the distribution points for KVI products. Further efforts are also been made to develop the Govt. Supplies and also create a helpline for bulk purchasers. Some of the major bulk Govt. orders received from Air India for amenity kits for International flights for herbal products like moisturizer, hand sanitizer, body wash, lip balm, essential oil, body soap etc. The Initial order received was to the tune of Rs. 1.25 crores. Similarly, orders for uniform including shoes and chappals for postal staff of Post and Telegraph, Uttarakhand has also been received. Bulk order from Indian Railway for Poly Khadi bedsheets, pillow covers are also expected. Estimated value is around Rs. 25 crores. As a part of increasing the sales outlets of Khadi, sales outlets is launched in the Consumer Stores of Aaykar Bhavan, Marine Lines, Murnbai on 10.02.2016 at 12.30 hrs.

An exclusive exhibition of Khadi & Village Industries products will also be organized in the Committee Room, ground floor of Aaykar Bhavan. Shri V. K. Saxena, Chairman, KVIC and Shri Devendra Saksena, Principal Chief Commissioner, Income Tax inaugurated the exhibition and the

खादी ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने के लिए और तीन कंपनियां निशाने पर

मुंबई, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने बिना अनुमति के 'खादी' ट्रेड नाम का इस्तेमाल करने वाली दो..तीन कंपनियों को नोटिस जारी करने की योजना बनाई है। आयोग पहले ही आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी मदुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल को खादी नाम का इस्तेमाल बंद करने के लिए नोटिस जारी कर चुका है। बिड़ला समूह की कंपनी ट्रेड मार्क के तौर पर खादी को बौद्धिक संपदा कानून के तहत पंजीकृत करा चुकी है। केवीआईसी चेयरमैन वी.के. सक्सेना ने आज यहां कहा, '' हम मदुरा फैशन को पहले ही नोटिस भेजकर बगैर अनुमति के खादी ट्रेड नाम का इस्तेमाल करना बंद करने को कह चुके है। हम इसी तरह के नोटिस और दो..तीन कंपनियों को भेजने पर काम कर रहे हैं।'' हालांकि, उन्होंने उन कंपनियों का नाम लेने से इनकार किया क्योंकि काम अभी प्रगति पर है। केवीआईसी के कारोबार के बारे में सक्सेना ने कहा, '' वर्तमान में केवीआईसी का सालाना कारोबार करीब 37,000 करोड़ रुपये का है और हमारी योजना इसे अगले साल 40,000 करोड़ रुपये ले जाने की है। उन्होंने कहा कि देश में इस समय 12.5 लाख खादी कामगार हैं और हमारी योजना अगले दो साल में इसे बढ़ाकर एक करोड़ पहुंचाने की है। सक्सेना ने कहा कि 'मेक इन इंडिया' नारों में विनिर्माण के जरिए ही संभव है।

खादी को आयकर विभाग बढ़ावा देगा

मुंबई। आयकर विभाग भी खादी को बढ़ावा देने के लिए आगे आया है। मुंबई के मरीन लाइंस स्थित आयकर भवन में बुधवार को खादी वस्तुओं की बिक्री के लिए कंज्यूमर स्टोर में एक बिक्री केंद्र खोला गया। इसके लिए आयकर विभाग और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के बीच करार हुआ है।

आयकर विभाग के प्रमुख आयुक्त देवेंद्र सक्सेना और आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया है। आयकर प्रमुख आयुक्त सक्सेना ने कहा कि यहां खादी की बिक्री अपेक्षा से अधिक होगी।

यह बिक्री केंद्र आयकर विभाग के दो हजार से अधिक कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करेगी।

THE HINDU

» Today's Paper » MUMBAI

Published: February 6, 2016 00:00 IST | Updated: February 6, 2016 05:39 IST February 6, 2016

Khadi outlet for I-T employees

The Khadi and Village Industries Commission (KVIC) of the State government is launching a sales outlet for khadi products as a pilot project at Aaykar Bhavan in Mumbai for Income Tax employees on February 10. An open-to-all exhibition of Khadi and Village Industries products will also be held at the Aaykar Bhavan.

कुशल हाथों द्वारा तैयार किए गये
ये प्राकृतिक, आकर्षक विशिष्ट और पारंपारिक वस्तुएं
मनमोहक होने के साथ-साथ विशुध्द, प्रामाणिक और
पोषक भी हैं । दशकों से खादी और ग्रामोद्योगी उत्पाद अपने
इन्हीं गुणों के लिए उपभोक्ताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय.
"इन्हे अपने दैनिक जीवन का अंग बनाएं"।

अपने नजदिकी खादी भवन /भंडार में अवश्य पधारें।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड, विले पारले (पश्चिम),मुंबई - 400056.
फोन: 2671 4320, 2671 6323 वेबसाइट : www.kvic.org.in